



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, २ सितम्बर, १९९४/११ भाद्रपद, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त (विनियम) विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, ३ अगस्त, १९९४

संख्या फिन-सी० ए० (३)-४/९४.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९९४ की धारा ९८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रवचनों के लिए राज्य वित्त प्रायोग के गठन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें उक्त अधिनियम की धारा १८६ की उप-धारा (३) के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण की जानकारी के लिए और उनके आक्षेप/सुझाव प्रामाणित करने के लिए प्रकाशन का प्रस्ताव करते हैं। सरकार द्वारा उक्त नियमों पर इसके प्रकाशन के पश्चात् ३० दिन की अवधि में विचार किया जाएगा। इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित कोई व्यक्ति यदि इनके विषय में कोई सुझाव/आक्षेप करना चाहें, तो वह उन्हें सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार को उक्त नियम अवधि में भेज सकता है। उक्त नियत अवधि में प्राप्त आक्षेप/सुझावों पर, यदि कोई हो, सरकार द्वारा उक्त आक्षेप नियमों को अन्तिम रूप देने में पूर्व विचार किया जाएगा :—

१. संक्षिप्त नाम.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंचायती राज अधिनियम के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त प्रायोग प्रम, १९९४ है।

२. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश प्रंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) "वित्त आयोग" से पंचायतों के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "राज्यपाल" से हिमाचल प्रदेश सरकार का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से वित्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत इसका अध्यक्ष भी है; और

(ङ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

3. अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति. — (1) हिमाचल प्रदेश सरकार, अधिनियम की धारा 98 के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के नाम से जातक्य राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

(2) वित्त आयोग का मुख्यालय जिसका में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।

4. वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :—

(क) पंचायतों से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो; और।

(ख) नगरपालिकाओं से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो; और

(ग) आर्थिक और प्रशासन मामलों का गहन अनुभव रखता हो; और

(घ) अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो।

5. वित्तीय या अन्य हित रखने वाले व्यक्तियों की अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा.— (1) सरकार, किसी व्यक्ति को वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए अपना समाधान करेगी कि ऐसा नियुक्त व्यक्ति, कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है जिससे वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके अपने कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(2) सरकार, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में समय-समय पर अपना समाधान करेगी कि वे कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखते हैं जिससे, वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके अपने कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो और सरकार इसका समाधान करने के लिए कि क्या कोई अध्यक्ष या सदस्य ऐसा हित रखता है, सरकार, अध्यक्ष और सदस्यों से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी वह उचित समझे।

6. वित्त आयोग के सदस्य होने के लिए निर्दिष्टताएँ.—कोई भी व्यक्ति, वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने या होने के लिए निर्दिष्ट होगा यदि वह :—

(क) विप्रेत भिन्न है;

(ख) अनुमोदित दिवसितया है;

(ग) नैतिक अधमता से ग्रस्त किसी अपराध में गिरफ्तार उद्धरया गया है;

(घ) कोई वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे वित्त आयोग के उनके अपने कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

7. सदस्यों की पदावधि.—वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा और पदावधि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा दो वर्ष में अनधिकृत छः मास के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

8. सेवा की शर्तें और सदस्यों के वेतन और भत्ते.—(1) राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति से पूर्व उन्हें बचन बद्ध करना होगा कि वह कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं रखेगा; जिससे उसकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनकी क्रिया कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(2) सदस्यों को सेवा की निवृत्ति और शर्तें उनकी पदावधि के दौरान उनके अहित में परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

(3) राज्य वित्त आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण से अवधि मान्य नहीं होगी कि इसके सदस्यों में से रिक्ति विद्यमान है या उनके संविधान में कोई त्रुटि है।

(4) राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अधिभावी होगी और आयोग की राय और प्रावेण बहुमत के विचारों के रूप में अभिव्यक्त किए जाएंगे।

(5) जब अध्यक्ष सरकार व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है तो वह वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो वह ऐसे पर ग्रहण करने में पूर्व प्राप्त कर रहा हो और यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो वह पेंशन को घटाकर वही वेतन और भत्ते प्राप्त करता रहेगा और अन्य मामलों में 3,000/- रुपये प्रति मास समेकित मानदेय संदत्त किया जाएगा।

6. जब सदस्य सरकार व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं तो वह अतिरिक्त किए गये वेतन जमा समय-समय पर यथा अनुज्ञेय भत्ते प्राप्त करेंगे और यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो वे पेंशन को घटाकर, अन्तिम लिए गये वेतन जमा समय-समय पर यथा अनुज्ञेय भत्ते प्राप्त करेंगे और अन्य मामलों में 4,000/- रुपये प्रतिमास समेकित मानदेय संदत्त किया जायेगा।

(7) अध्यक्ष और सदस्य ग्रंथ मुद्राजित आवाग प्राप्त करने के हकदार होंगे। वे सरकारी घरे पर यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते को उसी दर पर प्राप्त करने के हकदार होंगे जो सरकार के प्रथम श्रेणी के उच्चतम अधिकारियों को अनुज्ञेय होंगे। वे उसी मान पर शिक्षा मुद्राया प्राप्त करने के भी हकदार होंगे जो राज्य में तत्समय प्रवृत्त हों।

(8) मानदेय या वेतन, श्रेणी में केचित हो, और अन्य भत्ते राज्य सरकार की समेकित निधि में से चुकाए जाएंगे।

9. विस्तारयोग की प्रक्रिया और शक्तियाँ.—विस्तारयोग अपने कृत्यों के अनुपालन की क्रिया अवधारित करेगा और अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (7) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

10. राज्य वित्त आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय.—राज्य वित्त आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होगा जो राज्य सरकार के कार्यालय का होगा।

11. राज्य वित्त आयोग की मोहर और संप्रतीक.—राज्य आयोग की शासकीय मोहर और संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

12. राज्य वित्त आयोग की बैठक.—राज्य वित्त आयोग की बैठक जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी और वह कार्य के शीघ्र तथा निपटान के हित में, अपनी अधिकारिता में, किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकेगा।

13. राज्य वित्त आयोग के कर्मचारी.—राज्य सरकार, ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो आयोग को उसके दिन प्रति दिन कार्य में सहयोग देने और ऐसे हृत्प, जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं, का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हों। ऐसे कर्मचारियों को संदेय वेतन, राज्य सरकार की समेकित निधि में से चुकाया जाएगा।

14. पुनः नियुक्ति.—राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, इन नियमों के नियम 7 में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

15. अध्यक्ष और सदस्यों का पद से हटाया जाना और त्यागपत्र.—(1)—राज्य सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती जो :—

(क) न्यायनिर्णित दीवालिया हो, या

(ख) ऐसे अपराध से दोष सिद्ध किया गया हो जो राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता से अन्तर्बलित हो;

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो; या।

(घ) ऐसा वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर रखा हो, जिससे उसके अध्यक्ष या सदस्य के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में उचित न हो;

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए, अध्यक्ष या कोई सदस्य, उप-नियम के खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया, जो वह विनिर्दिष्ट करे, के अनुसार जांच नहीं कर ली जाती है, और अध्यक्ष या कोई सदस्य उक्त आधारों पर दोषी नहीं पाया जाता है।

आदेश द्वारा;

कंवर शमशेर सिंह;
विस्तारयोग एवं सचिव।

Authoritative English Text of the Notification No. Fin. C-A (3)-4/94, dated 3-8-1994 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India.

FINANCE (REGULATION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 3rd August, 1994

No. Fin.-C-A(3)-4/94.—In exercise of the powers conferred by section 98 of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules in relation to the constitution of the State Finance Commission for the purposes of the said Act and to publish the same, as is required under sub-section (3) of section 186, for the general information and for inviting public objections. The said rules shall be taken into consideration by the Government after 30 days of publication. If any person likely to be affected by these rules has suggestion or objection to make with regard to these rules, he may send the same to the Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh within the above stipulated period. Objections and suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government, before finalization of the said draft rules, namely :—

1. *Short title.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats Rules, 1994.

(2) These shall come into force at once.

2. *Definition.*— In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) “Act” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;
- (b) “Finance Commission” means the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayats constituted under Section 98 of the Act;
- (c) “Governor” means Governor of the State of Himachal Pradesh;
- (d) “Member” means a member of the Finance Commission and includes its Chairman; and
- (e) “Government” means the Government of Himachal Pradesh.

3. *Appointment of Chairman and Members.*—(1) The Government of Himachal Pradesh shall appoint a Chairman and two other Members of the State Finance Commission to be called the Himachal Pradesh State Finance Commission for Panchayat under section 98 of the Act;

(2) The Finance Commission shall have its headquarters at Shimla or as such other place as may be notified by the Government from time to time.

4. *Qualifications for appointment as Chairman and Members of Finance Commission.*—The persons to be appointed as Chairman of the Finance Commission as Members thereof shall—

- (i) have special knowledge and experience in economic and financial matters relating to Panchayats; or

- (b) have special knowledge and experience in economic and financial matters relating to Municipalities; or
- (c) have wide experience in financial matters and in administration; or
- (d) have special knowledge of economics.

5. *Persons having financial or other interests not to be appointed as Members of Finance Commission.*—(1) Before appointing a person as a Chairman or members of the Finance Commission, the Government shall satisfy itself that the person to be so appointed has no financial or any other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairman or Members of the Finance Commission.

(2) After the appointment of Chairman and Members of the Finance Commission, the Government may also satisfy itself from time to time with respect to the Chairman and Members of the Finance Commission that they may have no financial or any other interests as is likely to affect prejudicially their functions as Chairman or Members of the Finance Commission and for that purpose the Government may require the Chairman and the Members to furnish it such information as it may consider necessary with a view to satisfy himself as to whether the Chairman or the Members have any such interests.

6. *Disqualification for being Members of the Finance Commission.*—A person shall be disqualified for being appointed as, or for being a member of the Finance Commission:—

- (a) if he is of unsound mind;
- (b) if he is an undischarged insolvent;
- (c) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
- (d) if he has such financial or any other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member of the Finance Commission.

7. *Term of Office of Members.*—Every member of the Finance Commission shall hold office for one year and the term of office may be extended by a notification published in the official gazette at a time for six months, but not exceeding two years by the State Government.

8. *Conditions of service and salaries and allowances of Members.*—(1) Before appointment, the Chairman and Members of the State Finance Commission shall have to give an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairman or Members, as the case may be.

(2) The terms and conditions of service of the Members shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(3) No Act or proceedings of the State Finance Commission shall be invalid by reasons only of existence of any vacancy among its members or any defect in the constitution thereof.

(4) In case of difference of opinion among the members of the State Finance Commission, the opinion of the majority shall prevail and the opinion or orders of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority.

(5) Where the Chairman is appointed from amongst the serving persons, he shall draw the salary and allowances as he was drawing before assuming such office and if a retired person is appointed he shall continue to draw salary and allowances minus pension and in other cases a consolidated honorarium of Rs. 5,000/- per month will be paid.

(6) Where the Members are appointed from amongst the serving persons, they shall draw the pay last drawn by them plus allowances therein as admissible from time to time and if retired persons are appointed as Members they shall draw the pay last drawn by them minus pension plus allowances thereon as admissible from time to time and in other cases a consolidated honorarium of Rs. 4,000/- per month will be paid.

(7) The Chairman and the Members shall also be entitled to semi-furnished accommodation. They shall also be entitled for T.A. and D.A. on official tours at the same rates as are admissible to the highest Grade-I Officers of the Government. They shall also be entitled for medical facilities on the same norms as are for the time being applicable in the State.

(8) The honorarium or the salary, as the case may be, and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

9. *Procedure and Powers of Finance Commission.*—The Finance Commission shall determine its procedure in the performance of its functions and shall exercise the powers conferred upon it under sub-section (7) of section 98 of the Act.

10. *Working days and Office hours of the State Finance Commission.*—The working days and office hours of the State Finance Commission shall be the same as that of the offices of the State Government.

11. *Seal and emblem of the State Finance Commission.*—The official seal and emblem of the State Commission shall be such as the State Government may specify.

12. *Sitting of the State Finance Commission.*—The sitting of the State Finance Commission as and when necessary, shall be convened by the Chairman and it may, in the interest of speedy disposal of the work, hold its sittings at any place within its jurisdiction.

13. *Staff of the State Finance Commission.*—The State Government shall appoint such staff as may be necessary to assist the State Finance Commission in its day-to-day work and to perform such functions as are assigned to it by the Chairman. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

14. *Re-appointment.*—The Chairman and the Members of the State Finance Commission shall be eligible for re-appointment on the expiry of the time specified in rule 7 of these rules.

15. *Removal of Chairman or Members from Office and resignation.*—(1) The State Government may remove from office, the Chairman or any member who :—

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as the Chairman or Member; or
- (d) has acquired such financial or other interests as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairman or a Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in the office prejudicial to the public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairman or any Member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of that sub-rule except on an enquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and find the Chairman or any Member guilty on such grounds.

By order,

Sd/-

F. C. -cum-Secretary.

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th August, 1994

No. Rev. 2A (4) 2/93. —In continuation of this Department Notification of even number, dated 10th May 1994, vide which the period for submitting the report by the High Powered Committee constituted to investigate Benami Transactions was extended for three months. The Governor, Himachal Pradesh is pleased to further extend the time for submission of the report by 31st August, 1994.

By order,

P. T. WANGDI,

Financial Commissioner-cum-Secretary.

[authoritative English text of notification No. GAD(PA)-4(D)-9/38, dated 12th August, 1994, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th August, 1994

No. GAD(PA)-4(D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 15-11-1971 vide Notification No. 2-12/71-GAC, dated 31-8-1971, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Second Amendment Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment of rule 4.*—Proviso to rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971, shall be omitted.

By order,

S. S. NEGI.

Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 अगस्त, 1994

संख्या जी० ए० डी० (जी० ए०) 4(डी)-9/88. —हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 7 के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 15-10-71 के राजपत्र (प्रसाधारण) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या 2-13/71-जी० ए० डी०, तारीख 7 सितम्बर, 1971 द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव एसम्बली स्पीकर्स एण्ड डिप्टी स्पीकर्स (एडवांस फार मोटर कार) रूल, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बमाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव एसम्बली स्पीकर्स एण्ड डिप्टी स्पीकर्स (एडवांस फार मोटर कार) (सिफिड अमेंडमेंट) रूल, 1994 है।

(२) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

२. नियम ४ का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर (एडवांस फॉर मोटर कार) नियम, १९७१ क नियम ४ के परन्तु का कोश हटाया जाता है।

आदेश द्वारा,

एस ० एस ० नेगी,
अभ्युक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of notification No. GAD(PA)-4(D)9/88, dated 12th August, 1994, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th August, 1994

No. GAD(PA)4(D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 13 read with section 7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary) dated 15-10-1971 vide Notification No. 2-13/71-GAC, dated 7-9-1971, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Second Amendment Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment of rule 4.*—Proviso to rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 shall be omitted.

By order,

S. S. NEGI.
Commissioner-cum-Secretary.

नामाच्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-१७१००२, १२ अगस्त, १९९४

संख्या जी० ए० डी० (जी० ए० डी० ४(डी)-९/८८.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपसचिवों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, १९७१ (१९७१ का ५) की धारा ८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

तारीख 26-10-71 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में अधिनियम संख्या 2-14/71-जी० ए० सी०, तारीख 7 सितम्बर, 1971 द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश डिप्टी मिनिस्टर्स (एडवन्स फार मोटर कार) रूलज, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश डिप्टी मिनिस्टर्स (एडवन्स फार मोटर कार) सैविन्ड अमेंडमेंट रूलज, 1994 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश डिप्टी मिनिस्टर्स (एडवन्स फार मोटर कार) नियम, 1971 के नियम 4 के परस्त्वक का लोप किया जाता है।

आदेश द्वारा,

एस० एस० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of Notification No. GAD(PA)4(D)-9/88, dated 12th August, 1994, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th August, 1994

No. GAD (PA)-4 (D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Salaries and Allowance of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971 published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary) dated 26-10-1971, vide notification No. 2-14/71-GAC, dated 7-9-1971, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Second Amendment Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment of rule 4.*—Proviso to rule 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971 shall be omitted.

By order,

S. S. NEGI,
Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(संवर्द्धन कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 अगस्त, 1994

सं० जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)-9/88—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) को धारा 7-A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 31-3-81 के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०) 49/78-सां-जिल्द-II, तारीख 30-3-81 द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मिनिसटर्स (एडवान्स आफ लोन फार हाउस बिल्डिंग) रूल, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मिनिसटर्स (एडवान्स आफ लोन फार हाउस बिल्डिंग) (एमेंडमेंट) रूल, 1994 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मिनिसटर्स (एडवान्स आफ लोन फार हाउस बिल्डिंग) रूल, 1981 के नियम 4 के परन्तुन का लोप किया जाता है।

आदेश द्वारा,

एम० एस० नेगी

आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of Government Notification No. GAD (PA) 4 (D)-9/88, dated 12th August, 1994, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th August, 1994

No. GAD (PA) 4 (D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 7-A of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981, published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary) dated 31-3-1981 vide Notification No. GAD (PA)-4 (D) 49/78-C-Vol.-II. dated 30-3-1981, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Amendment Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment of rule 4.*—(2) Proviso to rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 shall be omitted.

By order,

S. S. NEGI,
Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 अगस्त, 1994

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) ४(डी)-९/३८.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उप मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, १९७१ (१९७१ का ५) की धारा ८-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख २६-३-१९८३ के राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) ४(डी०)-४६/८२, तारीख २२-२-१९८३ द्वारा प्रकाशित दि हिमाचल प्रदेश डिप्टी मिनिस्टर्स (एडवान्स आफ लोन फार हाऊस बिल्डिंग) रुलज, १९८२ में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश डिप्टी मिनिस्टर्स (एडवान्स आफ लोन फार हाऊस बिल्डिंग) (एमेंडमेंट) रुलज, १९९४ है।

(२) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

२. निधन ४ का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश डिप्टी मिनिस्टर्स (एडवान्स आफ लोन फार हाऊस बिल्डिंग) रुलज, १९८२ के निधन ४ के प्रारम्भ का लोप किया जाता है।

आदेश द्वारा,

एस० एस० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of the notification No. GAD(PA) 4 (D) 9/88, dated 12-8-94, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th August, 1994

No. GAD(PA) 4(D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 8(A) of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Deputy Minister (Advance of Loan for House Building)

Rules, 1982, published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary) dated 26-3-1983 vide Notification No. GAD (PA) 4 (D)-46/82, dated 22-2-1983, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Amendment Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment of rule 4.*—Proviso to rule 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1982 shall be omitted.

By order,

S. S. NEGI,
Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 अगस्त, 1994

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)-9/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 7-ए के साथ पत्र 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 17-4-1981 के राजपत्र (अधारण) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी०)-49/78-जी-भाग-11, तारीख 2-4-81 द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसम्बली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर (एडवान्स आफ लोन फार हाऊस बिल्डिंग) रूलज, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसम्बली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर (एडवान्स आफ लोन फार हाऊस बिल्डिंग) (एमेंडमेंट) रूलज, 1994 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसम्बली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर (एडवान्स आफ लोन फार हाऊस बिल्डिंग) रूलज, 1981 के नियम 4 के परन्तुक का लोप किया जाता है।

आदेश द्वारा,

एस० एस० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of notification No. GAD (PA) 4 (D)-9/88, dated 12-8-94 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th August, 1994

No. GAD (PA)-4 (D)-9/88.—In exercise of the powers conferred by section 13 read with section 7-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1271), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary) dated 17-4-1981 vide Notification No. GAD (PA)-4 (D)-46/82, dated 2-4-1981, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Amendment Rules, 1994.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment of rule 4.*—Proviso to rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 shall be omitted.

By order,

S. S. NEGI,
Commissioner-cum-Secretary.